भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1751
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का कार्यान्वयन

1751. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और डेयरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत मछुआरों और पशुपालकों को प्रदान की गई सहायता/राजसहायता का ब्यौरा क्या है और अनुसूचित वर्गों की महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन सहायता/राजसहायता से उत्पादन के प्रतिशत और लाभार्थियों की आय में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; (घ) छत्तीसगढ़ में मछली हैचरी, फीड यूनिट, शीत शृंखला और डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना की वर्तमान क्षमता कितनी है और क्षमता वृद्धि के लिए चिह्नित किए गए विशिष्ट क्षेत्रों / जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निगरानी और मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर छत्तीसगढ़ में उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में मात्स्यिकी, पशुधन और डेयरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) और डेयरी विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यान्वित इन योजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति अनुबंध-I में प्रस्तुत की गई है। इन योजनाओं को लागू करते समय, महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभार्थियों पर विशेष जोर दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में मत्स्य उत्पादन में सुधार हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फिश सीड का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 288 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 583 करोड़ हो गया है, जो लगभग 102.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि इसी अवधि के दौरान मत्स्य उत्पादन 5.72 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 8.73 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो लगभग 52.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और संबद्ध डेयरी हस्तक्षेपों के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में दूध का उत्पादन 2014-15 में 11.82 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 20.76 लाख टन हो गया है। उत्पादन में वृद्धि ने लाभार्थियों की आय और आजीविका सुरक्षा की वृद्धि में योगदान दिया है;

(घ): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, राज्य ने मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया है। कुल 25 फिश हैचरी स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 21 हैचरी पूरी हो चुकी हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। फिश फीड विनिर्माण का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया गया है और राज्य में वर्तमान में 100 टन प्रतिदिन क्षमता की एक फीड मिल, 20 टन प्रतिदिन क्षमता के दो फीड संयंत्र, 8 टन प्रतिदिन क्षमता के पांच फीड संयंत्र और 2 टन प्रतिदिन क्षमता की दो लघु फीड मिल हैं।

(ड): स्वीकृत परियोजनाओं के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने PMMSY और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं के लिए बहु-स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन (M&E) तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल निगरानी, PFMS पोर्टल शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का प्रभावी ढंग से उपयोग हो और परियोजनाएं समय पर पूरी हों, स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा/निगरानी हो। इसके अलावा, संबंधित विभाग समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और नोडल कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। भारत सरकार आगे विस्तार शुरू करने से पहले प्रत्येक योजना का मध्यावधि और पूर्ण अवधि का तृतीय-पक्ष से मूल्यांकन अध्ययन भी कराती है। परिणामों और मूल्यांकन रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर, प्रभावी कार्यान्वयन और भावी नीतिगत उपायों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

****

अनुबंध I

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के कार्यान्वयन के संबंध में 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय स्थिति।

योजना	महिला लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित श्रेणी में लाभार्थियों की संख्या	परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति	वित्तीय स्थिति (केन्द्रीय/भारत सरकार की सहायता)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)	6800	10500	94 परियोजनाएं स्वीकृत; परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं	कुल परियोजना लागत 92,478.45 लाख रुपए; केंद्रीय शेयर जारी 23,859.24 लाख रुपए; केंद्रीय शेयर का उपयोग 22,097.15 लाख रुपए
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)	814184	उपलब्ध नहीं है *	225 MAITRIs को प्रशिक्षित किया गया; 27,08,364 कृत्रिम गर्भाधान किया गया; 19,66,094 पशुओं को कवर किया गया; NAIP के अंतर्गत 11,63,120 किसान लाभान्वित हुए।	विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 1,161.69 लाख रुपए जारी किए गए
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)	6	5	7365 पशुधन को शामिल किया जा रहा है और 2400 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) साइलेज क्षमता जोड़ी जा रही है।	NLM EDP के अंतर्गत 16.50 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन 27 परियोजनाओं के लिए कुल स्वीकृत सब्सिडी 6.19 करोड़ रुपए है। 1.89 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)	0	0	686.06 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।	3 प्रतिशत के ब्याज अनुदान के रूप में कुल 21.44 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
डेयरी विकास कार्यक्रम	**	**	48.71 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें से 34.76 करोड़ रुपए का केंद्रीय शेयर है	कुल 19.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं

* NAIP के तहत अनुसूचित श्रेणी सहित 1163120 किसान लाभान्वित हुए है।

** लाभार्थी योजना नहीं है

******